नए साल में समाज में बढ़े सद्भावना, चरमोत्कर्ष पर पहुंचे देश

प्रशांत मिश्र

नए साल का स्वागत है, इस आशा के साथ कि समाज में सद्भावना और समृद्धि बढ़े, हर हाथ को रोजगार मिले, हर व्यक्ति शिक्षित व स्वस्थ हो और देश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। हमारे देश में इतनी प्रतिभा और संभावना है कि हम इसे न सिर्फ हासिल करें बल्कि तय समय सीमा में हासिल करें। पर इसकी एक बड़ी शर्त है कि हम हर हाल में एकजुट हों, खुद से पहले देश की सोचें और खासकर राजनीति को अपनी व्यक्तिगत सोच पर हावी न होने दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते हुए साल में बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं, बड़े फैसले हुए, बड़ी पहल हुई और हां, जनता ने दशकों बाद अभूतपूर्व जनादेश देकर यह जताया कि सरकार उनकी अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों ने ऐसा माहौल बनाया, जिसमें ऐसा महसूस कराने की कोशिश हुई कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि पीछे की ओर खिसक रहा है। यह राजनीतिक छाया है, जिससे हमें अपनी सोच को बचाना होगा।

2019 में राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी घटना लोकसभा चुनाव नतीजा ही था, जिसने यह स्थापित किया कि सरकारों के खिलाफ केवल सत्ताविरोधी लहर ही नहीं सत्ता के पक्ष में भी लहर होती है। यह तब परिलक्षित होता है, जब सरकारें महात्मा गांधी की सोच के अनुसार अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचती हैं और इसका भी ध्यान रखती हैं कि निम्न से उच्च वर्ग तक के विकास का संतुलन बना रहे। 2014-19 के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कुछ किया था, जनता ने उसका रिपोर्ट दिया। हालांकि मोदी सरकार के आलोचकों ने इसका पूरा श्रेय केवल बालाकोट हमले को दिया। जो भी हो बालाकोट ने यह जरूर तय कर दिया कि भारत सोते रहने वाला देश नहीं है। भारत धैर्य रखना जानता है, लेकिन

आगाज 2020

- प्रतिभा और संभावना के दम पर हासिल कर सकते हैं लक्ष्य
- बीते हुए साल में बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं, बड़े फैसले हुए

कायर नहीं है और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। यह भारत के इतिहास को बदलने वाली घटना थी। 2019 इसके लिए याद किया जाता रहेगा। लेकिन भारी जनादेश के साथ दोबारा सत्ता में लौटी मोदी सरकार ने मानो यह तय कर लिया था कि 2019 बालाकोट के जरिये मानसिकता को बदलने वाले साल के लिए नहीं बल्कि तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध के जरिये मुस्लिम समाज की रूढ़ि, अनुच्छेद 370 के जरिये जम्मू-कश्मीर में वर्षों के अलगाव को मिटाने, नागरिकता संशोधन कानून के जरिये शरणार्थियों की पीड़ा को दूर करने के साल के रूप में याद किया जाएगा। अपने गठन के बाद तत्काल जिस गति से सरकार इन मुद्दों पर आगे बढ़ी वह इसी की ओर इशारा करती है। यह और बात है कि विपक्ष ने इन मुद्दों को नकारात्मक तरीके से देखा और यही कारण है कि साल के अंतिम दिनों में कुछ स्थानों पर हिंसा फैली। राजनीतिक दलों की गलत सोच का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से लंबित राम मंदिर पर फैसला देकर एक मुद्दे को अच्छी तरह सुलझाया तो उस पर भी अंगुली उठाई गई। यही कारण है कि हमें नए साल में खुद पर विश्वास करने, खुद की सोच को विकसित करने पर जोर देना होगा।

खैर, ये बातें बीत गई हैं। जो मुद्दे राजनीतिक दलों के पाले में हैं, उस पर भी जनता ही आखिरी फैसला करेगी। लेकिन नए साल में सरकार से आशाएं भी हैं। जब जनादेश अभूतपूर्व होता है तो अपेक्षाएं भी अनगिनत होती हैं। आर्थिक हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं। रोजगार के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी आयकर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले मध्यमवर्ग के बोझ को कम करने की बात करते रहे हैं, लेकिन वह कदम अभी अधूरा है। जनता को ये मुद्दे चुभ रहे हैं। मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है लेकिन जनता परोक्ष रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में यह जता भी चुकी है कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है।

यह सच है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व पर जनादेश आता है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि 2014 में जब इन तीनों राज्यों में भाजपा ने इतिहास रचा था तो वह मोदी का करिश्मा था। भाजपा अब मोदी के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकते हैं और उन्हें फिर से साबित करना होगा कि वह इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाने के लिए देशभर से सैलानी पहुंचे हैं। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पर्यटकों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। मंगलवार को सैलानियों ने बर्फ पर संदेश लिखकर कश्मीरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। एएनआइ

नए साल में कटड़ा में श्रद्धालु और गुलमर्ग में उमड़े सैलानी

जेएनएन, नई दिल्ली

- वृंदावन और गोवर्धन में भी जुटे लोग, होटल और धर्मशाला फुल

नए साल की शुरुआत नये जम्मू कश्मीर से करने को लेकर देशभर के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। विशेषकर जम्मू का पर्यटक स्थल पर्यटकों से पूरी तरह पैक रहा। उधर, कश्मीर के गुलमर्ग में पंद्रह दिन पहले ही सैलानियों का पहुंचना शुरू हो चुका था। यहां भी बर्फ से ढकी चोटियों के बीच सैलानियों ने नये साल का स्वागत किया। वहीं, माता वैष्णो देवी के चरणों से नये साल की शुरुआत करने वाले श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ उमड़ी। मंगलवार देर शाम तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर यात्रा शुरू कर चुके थे। आलम यह था कि कटड़ा में दर्शनी ड्योढ़ी और भवन पर दिनभर एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी कतारें लगी रहीं। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को 43,123 श्रद्धालुओं माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। पर्यटन विभाग ने 31 दिसंबर को गुलमर्ग में विशेष आयोजन किए थे। श्रीनगर में भी डल झील के किनारे देर शाम सैलानी एक-दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते नजर आए। जम्मू से करीब 120 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटनस्थल पत्नीटॉप में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रही। पत्नीटॉप के मैदान में तीन से चार फीट और साथ लगते नत्थाटॉप में भी छह से सात फीट बर्फ जमा है। नए साल के आगाज को लेकर शिमला में भी काफी अधिक भीड़ रही। युवा टोलियों में घूमकर और नाच-गाकर जश्न मनाते रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और गोकुल के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर देश-विदेश के लोग नए साल की शुरुआत करने वालों की तादाद भी काफी रही।

सैलानियों में दिखा जोश व उत्साह : नए साल की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करने के लिए, हालांकि हर साल सैलानी आते हैं, लेकिन इस बार केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पर्यटकों में अलग ही उत्साह नजर आया। गुलमर्ग में नोएडा, गुजरात, मुंबई, बंगाल से भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे।

मसूरी-नैनीताल में उमड़े लोग

मसूरी, चकराता, औली और नैनीताल में भी सैलानियों को सैलाब उमड़ पड़ा है। मसूरी में होटल, लॉज और धर्मशालाओं में 80 फीसद कमरे भर चुके हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक आसपास के स्थलों धनोल्टी, काणाताल और चकराता भी पहुंचे। मसूरी में सुबह से ही सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मसूरी में भीड़ को नियंत्रित करने के यातायात प्लान बनाया गया है। मसूरी के होटलियर व उत्तराखंड होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप साहनी के अनुसार होटलों ने पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था की है। इसके तहत कुछ बड़े होटलों में लाइव बैंड, डिनर और डांस की व्यवस्था की गई है।

'गगन' से जुड़ा क्रिस देगा ट्रेनों की सटीक जानकारी

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर : नए साल में रेल यात्रियों को नई सौगात मिली है। कोहरा हो या ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, गाड़ियों का निरस्तीकरण या विलंबन। यात्रियों के लिए घर बैठे किसी भी मोबाइल या नेट फीचर पर (गूगल, अन्य वेबसाइट, एप या 139 आदि) ट्रेनों की सटीक ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है।

रेलवे ने इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) से हाथ मिलाया है। इसरो की मदद से रेलवे का सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) रिसीवर गगन के जरिए सीधे सैटेलाइट से जुड़ गया है। इसरो सैटेलाइट के माध्यम से हर क्षेत्र से एकत्र डाटा अलग-अलग सिस्टम में क्रिस को उपलब्ध करा रहा है और क्रिस इसे आम यात्रियों तक पहुंचा रहा है।

रेल मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड और इसरो के बीच दिसंबर 2017 में अनुबंध हुआ था। इसरो ने जी-सैट सीरीज के सैटेलाइट की मदद से एक डिवाइस विकसित कर रिसीवर गगन से लिंकअप कर दिया है। अब क्रिस और सैटेलाइट आपस में जुड़ गए हैं। फिलहाल, भारतीय रेलवे में यह नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। स्वयं रेलमंत्री पीयूष गोयल क्रिस और इसरो की उपलब्धि को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।

इसरो से जुड़ने से पहले बोर्ड ने भारतीय रेलवे की ऑनलाइन मैपिंग कराई है। यानी सभी रेल लाइनों, स्टेशनों, ट्रेनों और परिसर का आन लाइन नक्शा तैयार है, जो एक प्लेटफार्म पर मौजूद है।

जम्मू-कश्मीर में आज से एक टैक्स

बड़ा तोहफा ▶ दोहरी कर व्यवस्था समाप्त, लखनपुर टोल टैक्स हटाया गया

जागरण संवाददाता, जम्मू

- रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित सभी टोल पोस्ट भी हटाए गए
- ढाई साल से लोग खरीद पर जीएसटी के साथ राज्य में लगने वाला टोल टैक्स भी कर रहे थे अदा

नये जम्मू-कश्मीर को नव वर्ष पर बड़ा तोहफा मिला है। पहली जनवरी 2020 से राज्य के लोगों पर पड़ रही दोहरे टैक्स की मार खत्म हो जाएगी। बुधवार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक टैक्स प्रणाली लागू हो जाएगी। राज्य के प्रवेशद्वार लखनपुर के साथ ही रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित सभी टोल पोस्टों को हटा दिया गया है। लखनपुर, रेलवे व हवाई मार्ग से जो भी सामान आता था, उस पर टोल टैक्स लगता था, जिससे अब मुक्ति मिल गई है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर वित्तीय विभाग की ओर से मंगलवार को दो अधिसूचना जारी की गई।

जम्मू-कश्मीर में ढाई साल से लोग हर खरीद पर जीएसटी अदा करने के साथ कुछ चीजों को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाले सभी सामान पर न्यूनतम 100 रुपये प्रति क्विंटल टोल टैक्स भी दे रहे थे। वस्तुओं पर टोल टैक्स खत्म होने का सबसे अधिक फायदा निर्माण सामग्री की खरीद में होगा। सीमेंट का 50 किलोग्राम का बैग अब जम्मू-कश्मीर में करीब 50 रुपये सस्ता हो जाएगा। इससे पूर्व बाहर से आने वाले सीमेंट पर 50 रुपये प्रति बैग टोल लगता था, जो अब नहीं लगेगा। इसी तरह स्टील के दाम में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आ जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाले प्लाइवुड व अन्य फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर टोल टैक्स हटने से अधिक फायदा होगा।

अनुच्छेद- 370 के तहत जारी था टोल टैक्स : एक जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने एक दर्जन से अधिक केंद्रीय व राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों को समाप्त करते हुए वन-नेशन, वन-टैक्स के रूप में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू किया था, लेकिन अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंच कर इसने दम तोड़ दिया। जब पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली लागू हुई, उस समय जम्मू के व्यापारी जीएसटी लागू करने की मांग को लेकर वेयर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार एक सप्ताह बाद तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जेएंडके जीएसटी बिल पारित किया और आठ जुलाई 2017 से जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ। तत्कालीन सरकार ने लखनपुर में वस्तुओं पर टोल टैक्स को जारी रखा, जिससे व्यापार जगत को करारा झटका लगा। दो साल तक व्यापार जगत इसे हटाने की मांग को लेकर संघर्षरत रहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद- 370 व 35ए समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने का फैसला लिया तो उम्मीद जगी कि जम्मू-कश्मीर को दोहरे टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। अब नए साल के तोहफे के रूप में लोगों को लखनपुर टोल टैक्स से मुक्ति मिली है।

राज्य सरकार को होती थी सालाना 1500 करोड़ की आय

सामान पर टोल टैक्स लगने से जम्मू-कश्मीर सरकार को सालाना 1500 करोड़ रुपये की आय होती थी। इसमें सबसे ज्यादा लखनपुर में सालाना 644.64 करोड़ रुपये मिलते थे। रेलवे और हवाई मार्ग सहित अन्य सभी टोल टैक्स को मिलाकर कुल कमाई 1500 करोड़ के आसपास बैठती थी। अब राज्य की यहआय समाप्त हो जाएगी।

किस पर कितना लगता था टोल टैक्स

टेक्सटाइल व भेड़ बकरियां	175 रुपये प्रति क्विंटल
खाद्य तेल	235 रुपये प्रति क्विंटल
सिगरेट	4000 रुपये प्रति क्विंटल
तंबाकू (चबाने वाले को छोड़कर)	400 रुपये प्रति क्विंटल
फ्रोजन चिकन	900 रुपये प्रति क्विंटल
बादाम, अखरोट, केसर व खुबानी	235 रुपये प्रति क्विंटल
ब्रेड	एक रुपये प्रति ब्रेड
(इन्हें छोड़ अन्य सभी वस्तुएं : 100 रुपये प्रति क्विंटल)	

इन वस्तुओं पर नहीं था टोल टैक्स

दालें, आटा, चावल, मैदा, सूजी, चीनी, चावल (सभी नान ब्रांडेड), आलू-प्याज, कश्मीर से निर्यात होने वाले सेब व सब्जियां

ये सामान होंगे सबसे ज्यादा सस्ते : सीमेंट, स्टील, प्लाइवुड, फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, टेक्सटाइल, भेड़ बकरियां, खाद्य तेल, सिगरेट, तंबाकू (चबाने वाले को छोड़कर), फ्रोजन चिकन, बादाम, अखरोट, केसर व खुबानी और ब्रेड

कश्मीर में एसएमएस सेवा बहाल, मोबाइल इंटरनेट शुरू होने की भी उम्मीद

नए साल का तोहफा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर को नये साल का तोहफा देते हुए वादी में मोबाइल पर एसएमएस सेवा और सरकारी अस्पतालों में ब्राडबैंड सेवा को बहाल कर दिया है। अब कश्मीर के लोग अपने मोबाइल से परिजनों को नए साल पर बधाई संदेश भेज सकेंगे। इसकी घोषणा राज्य सरकार के प्रवक्ता व योजना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने मंगलवार शाम को की। इस बीच, राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एक बयान में कहा कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हो जाएगी।

जम्मू के मीडिया कांप्लेक्स में संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर में मध्य रात्रि से एसएमएस सेवा और अस्पतालों में ब्रांडबैंड सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर के जिला मुख्यालयों में चुने हुए 900 स्थानों पर स्थापित इंटरनेट टच प्वाइंट पर इस समय लोगों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छह लाख के करीब विद्यार्थी, टूर ऑपरेटर, व्यापारी व ठेकेदार अब तक इसका लाभ उठा चुके हैं। सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा और कश्मीर व जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में मोबाइल सेवा बंद की थी। कुछ समय पहले कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई थी। प्री-पेड सेवा अभी भी बंद है। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

सेब खरीद की तिथि बढ़ाई गई : रोहित कंसल ने बताया कि कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत नेफेड के बागवानों से सेब खरीदने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। उद्योग को बढ़ावा देने को सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए कंसल ने बताया कि सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन किया जाएगा।

योजना विभाग के प्रमुख सचिव और सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार शाम पत्रकारवार्ता में जम्मू कश्मीर में टोल टैक्स समाप्त करने और कश्मीर में एसएमएस सेवा शुरू करने की घोषणा की। उनके साथ हैं सूचना विभाग की निदेशक सैयद सहरिश असगर। जागरण

नेताओं की रिहाई पर प्रशासन लेगा फैसला

कश्मीर में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं की हिरासत को कानून व्यवस्था का मसला करार देते हुए रोहित कंसल ने कहा कि यह स्थानीय प्रशासन का फैसला है। इस पर समय-समय पर गौर किया जाता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सोमवार को कुछ नेताओं को छोड़ा गया था। प्रशासन आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। इस मौके पर उनके साथ सूचना विभाग की निदेशक डॉ. सईद सहरीश असगर भी मौजूद थी।

इस साल चंद्रयान-3 लांच करेगा भारत

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत 2020 में चंद्रयान-3 लांच करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पर चंद्रयान-2 से कम लागत आएगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 को विफल कहना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का भारत का यह पहला प्रयास था। दुनिया में कोई देश आज तक अपने पहले प्रयास में चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया है। अमेरिका ने कई बार प्रयास किए। हालांकि, हमें उतनी बार कोशिश नहीं करनी पड़ेगी।

सिंह ने कहा कि चंद्रयान-2 से मिले आंकड़ों और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के चलते चंद्रयान-3 पर कम लागत आएगी। उन्होंने हालांकि तीसरा चंद्र मिशन किस महीने लांच किया जाएगा, इसके बारे बताने से इन्कार कर दिया। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-2 में इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई थी।

भारत को 2020 में और सशक्त बनाने की उम्मीद : पीएम मोदी

- 2019 में केंद्र की उपलब्धियों पर बना गाना, पीएम ने किया वीडियो ट्वीट
- राष्ट्रपति ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नववर्ष 2020 भी भारतीयों के जीवन को और सशक्त बनाएगा। साथ ही नए साल में भारत को बदलने के जनशक्ति आधारित प्रयास भी जारी रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लोगों को शांतिपूर्ण, देखरेख करने वाले और दयालु समाज को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होने की अपील की है।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो 2.0 ट्विटर हैंडल के एक गाने के वीडियो को री-ट्वीट किया। केंद्र सरकार की 2019 की उपलब्धियों के जिक्र वाले इस गाने को मोदी के प्रशंसकों ने तैयार किया है। पीएम मोदी ने इस वीडियो की सराहना करते हुए कहा कि इस साल भारत ने कई उपलब्धियों को हासिल किया और कई जगहों पर हमें विफलता भी मिली। साल की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही, पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 44 वीर जवान शहीद हो गए, जिसका बदला पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लिया गया।

नमो 2.0 ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर इस गाने का वीडियो लिंक शेयर किया और लिखा, '2019 भारत के लिए एक अद्भुत वर्ष था। हमने उन चीजों को बदल दिया जो हमने सोचा था कि कभी नहीं बदल सकते। हमने वो चीजें हासिल कीं जो हमने कभी नहीं सोचा था। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे नरेंद्र मोदी जी।'

इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट को री-ट्वीट कर लिखा, 'प्यारा संकलन! 2019 में हमने काफी प्रगति हासिल की है। यहां उम्मीद है कि 2020 तक भारत को बदलने और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए संचालित लोगों के प्रयासों को जारी रखा जाएगा।'

इस बीच, राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नए साल और नए दशक के आगमन पर हम सब को अधिक सशक्त और समृद्ध भारत के लिए प्रतिबद्धता को नए सिरे से दिखाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण, देखरेख करने वाले और दयालु समाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

नरेंद्र मोदी। फाइल

ओडिशा में रात एक बजे तक शराब की दुकान खोलने के फैसले का विरोध

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर (ओडिशा) : जीरो नाइट सेलिब्रेशन के लिए रात एक बजे तक बार और शराब दुकान खोले रखने के ओडिशा सरकार के निर्णय का कांग्रेस और भाजपा ने विरोध किया है। कांग्रेस के विधायक संतोष सिंह सलूजा ने कहा कि सरकार की यह नीति दोहरी है। एक तरफ सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना लगा रही है। ऐसे लोगों को जेल भेजने की बात कर रही है वहीं, रात एक बजे तक जश्न मनाने के लिए शराब दुकान खोल रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाने से जो दुर्घटनाएं होंगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। सरकार के पास राजस्व की कमी हो गई है, इस कारण ऐसा कदम उठा रही है।

उधर, आबकारी मंत्री निरंजन पुजारी ने कहा कि यह केवल नए साल के लिए लागू किया गया है। भुवनेश्वर, पुरी, कटक में नए साल पर रात एक बजे तक शराब दुकान खुली रहेंगी। इस संदर्भ में आबकारी विभाग के अतिरिक्त सचिव ने आबकारी कमिश्नर को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इस साल पहली बार राज्य सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है, जिसका कांग्रेस व भाजपा विरोध कर रही है। हालांकि, राज्य सरकार के इस निर्णय का बार मालिकों ने स्वागत किया है। वहीं, बुद्धिजीवियों ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता प्रताप सारंगी ने राज्य सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है।

अयोध्या में वह सुबह आ गई, जिसका सदियों से था इंतजार

रघुवरशरण, अयोध्या

- राममंदिर के साथ पूरी नगरी के भव्यतम होने की उम्मीद के साथ नववर्ष में हो रहा प्रवेश

रामनगरी की यह सुबह बहुप्रतीक्षित थी। 492 वर्ष से न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि विश्वभर के रामभक्त इस सुबह का इंतजार कर रहे थे। यह उस साल की पहली सुबह है, जिसमें रामनगरी के भव्यतम स्वरूप की आधारशिला रखी जानी है। यूं तो रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण तो गत नौ नवंबर को आए सुप्रीम फैसले से ही तय हो गया है लेकिन, नव वर्ष के पूर्वार्ध में इसकी शुरुआत होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए शासकीय न्यास के गठन की बात कही है। इस हिसाब से आठ फरवरी तक इसका गठन हो जाना है। इसके बाद मंदिर निर्माण शुरू होने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। शासकीय न्यास के गठन और मंदिर निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सरकार गंभीर है। मंदिर निर्माण के प्रति उत्साह के साथ उसके भव्यतम आकार-प्रकार की कल्पना भी की जा रही है। स्वयं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो बार रामलला के गगनचुंबी मंदिर निर्माण का भरोसा दिला चुके हैं। कई अन्य मंदिर समर्थक रामलला के भव्यतम मंदिर की चाहत का इजहार कर रहे हैं। कोई रामलला के 1008 फीट ऊंचे मंदिर की मांग कर रहा है, तो कोई 1011 फीट। यह कहना तो कठिन है कि रामलला का मंदिर कितना ऊंचा होगा पर यह विश्वास पक्का होता जा रहा है कि यह अति भव्य होगा। 2020 में ही रामनगरी को अति भव्यता की पर्याय भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास का इंतजार होगा। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी।

रेलवे स्टेशन पर खर्च होंगे दो सौ करोड़ : स्थानीय रेलवे स्टेशन को एक साथ 50 हजार यात्रियों के बैठने के हिसाब से विस्तार दिया जा रहा है। 80 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन के विकास का काम 2018 से ही शुरू है और अब इसे दो सौ करोड़ की लागत से विकसित किया जाना है।

कायाकल्प के लिए त्रिस्तरीय मास्टर प्लान तैयार

प्रशासन ने रामनगरी के त्रिस्तरीय विकास का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका प्रारंभिक चरण निर्णय के छह माह बाद, मध्य का चरण निर्णय आने के दो साल बाद और अंतिम चरण छह साल में पूरा करने का लक्ष्य तय है। ऐसे में यह तय है कि अगले कुछ सालों में रामनगरी दुनिया को अपनी आभा से लुभाएगी और अयोध्या नगरी का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक ...ग्राहकों का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: कौशाम्बी, गाजियाबाद, फोन: 0120-2776289/0120-2774804, ई-मेल: bo3000@pnb.co.in
कब्जा सूचना [नियम 8(1)]
चूंकि, पंजाब नैशनल बैंक, बीओ: कौशाम्बी, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'उक्त एक्ट' के रूप में ज्ञात) के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार श्री शर्मन्द कुमार एवं रूपी सिंह (एकाउंट नं. 300000KC00005234) को मांग सूचना दिनांक 03.10.2019 एवं 13(2) दिनांक 11.10.2019 को जारी किया जिसमें कहा गया कि उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत, इस सूचना मिलने की तिथि से 60 दिन के भीतर, यथाकथित राशि का भुगतान नहीं होगा है, उस पर भावी ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 24,97,044/- (रुपये चौबीस लाख सैंतानवे हजार चौवालिस मात्र) (30.09.2019 तक ब्याज समेत) का भुगतान करें।
कर्जदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे। एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 28 दिसंबर, 2019 को उक्त नियमावली की नियम 9 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
जनसाधारण एवं विशेषकर कर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी की कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं कोई लेनदेन पूर्ण भुगतान नहीं होता है, उस पर भावी ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 24,97,044/- (रुपये चौबीस लाख सैंतानवे हजार चौवालिस मात्र) (30.09.2019 तक ब्याज समेत) की राशि हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार में होगी।
अचल संपत्ति का विवरण
ईएम. भ.सं. 605, पांचवा तल, टाईप ए-1, ब्लॉक गोदावरी, आनन्द आश्रय काम्प्लेक्स, जीएच-07ए, सेक्टर Phi-02, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.)
दिनांक: 28.12.2019, स्थान: गाजियाबाद
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक